मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 64 | जनवरी, 2019 | अंक 1 | कुल पृष्ठ 8

डॉ० पंजाबराव देशमुख जी की 120वीं जयंती पर भारत कृषक समाज की श्रद्धांजलि

इस वर्ष हमने 27 दिसंबर, 2018 को डॉ० पंजाबराव देशमुख जी की 120वीं जयंती मनाई। वे भारत कृषक समाज के संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दिन पूरे देश में हम और भारत कृषक समाज की सभी शाखाऐं उनके कार्यों और उनके विचारों को स्मरण करने के लिऐ बैठकें और गोष्ठियां, वार्तालाप और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। डॉ० देशमुख ने भारत कृषक समाज के बीज बोऐ थे और अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करके इसे सशक्त बनाया। इस दिन हम उन्हें देश के शोषित किसानों के एक अगुवा और मजबूत नेता के रूप में याद करते हैं। डॉ० देशमुख जिन आदर्शों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिऐ अपना पूरा जीवन लड़े वे अभी भी पूरे नहीं हुऐ और न ही उनकी प्राप्ति हो पाई। यह युद्ध अभी चल रहा है। हम आज भी शोषित, पिछड़े और गरीब किसानों तथा खेतीहर मजदूरों के कल्याण और उन्नति के लिऐ संघर्ष कर रहे हैं और सभी जोखिमों और कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। हम उन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं जिनके लिऐ हमारे नेता डॉ० पंजाबराव देशमुख ने संघर्ष किया था।

डॉ० देशमुख गांधी जी, नेहरू जी और डॉ० राजेन्द्र प्रसाद तथा अन्य निःस्वार्थ राष्ट्रीय नेताओं के समय के प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उन्होंने इन नेताओं के बताऐ हुऐ मार्ग को ईमानदारी से अपनाया और इसका परिणाम भी आया तथा भारत की सबसे पहली और बड़ी किसानों की संस्था 'भारत कृषक समाज' की स्थापना की। आज भारत कृषक समाज के 1 लाख से भी अधिक सदस्य हैं। जब डॉ० देशमुख ने किसानों के कल्याण के लिऐ शुरूआत की थी उस समय किसानों की स्थिति निराशाजनक और बदतर थी। उन्होंने इस चुनौती को सविकार किया और किसानों को भारत कृषक समाज के बैनर के तले संगठित किया। वे स्वंय एक किसान थे और उन्होंने अंग्रेजों के समय के अत्याचार और निर्धनता देखी थी, जब किसानों के पास पहनने को कपड़े नहीं और खाने को अनाज भी नहीं था। इस दिशा में उन्होंने सबसे पहले किसानों की नई पीढ़ी

को शिक्षित करना उचित समझा ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्होंने इंग्लैंड से शिक्षा ग्रहण की और कानून की पढ़ाई करने के बाद लोगों की सेवा में जुट गऐ। महाराष्ट्र में अमरावती के एक छोटे से गांव में पैदा हुऐ वे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री के पद तक पहुंचे। हमें उनकी 120वीं जयंती के मंगल दिवस पर यह प्रतिज्ञा करनी चाहिऐ कि हम उनके आदर्शों और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे तथा इसके लिऐ संघर्षरत रहेंगे।

– अजय वीर **जाखड़**
अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

सभापति का पत्र :

आशाविहिन ग्रामीण परिदृश्य में चिंता उभर रही है और यह आक्रोश किसी भी समय अत्यधिक क्रोध में बदल सकता है। कृषि से उपजी संकट की स्थिति एक ऐसी चरमसीमा पर पहुंच चुकी है, जहां पर अब मोदी जी जो कुछ भी कहें उस पर विश्वास करना कठिन होता है।

यह समझने के लिऐ कि किसानों की प्रतिक्रिया और आक्रोश को भुनाने के लिऐ राजनैतिक दल वर्ष 2019 में किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं, इसके लिऐ 'किसान' की परिभाषा को समझना अनिवार्य है। पिछले काफी समय से किसानों की पहचान लगभग खो चुकी है। लगभग पूरे भारत में किसान की अब पहचान नहीं रह गई है। अब कई स्तरों पर पहचान बन रही है, जो कि अवसर और प्रसंग के अनुसार ग्रामीणों की पहचान धर्म, जाति, भाषा, व्यवसाय, क्षेत्र, जमीनदार अथवा भूमिहीन, जो सरकारी नौकरी में हैं अथवा नौकरी के इच्छुक होते हैं, के आधार पर की जाती है।

गांव में कृषि आधारित आजीविका पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है और यह वाणिज्यिकरण और बाजार पहलूओं पर समान रूप से निर्भर है। उत्पादन बढाने की चाह में कृषि विश्वविद्यालय एक विशेष क्षेत्र में एक ही फसल उगाने पर ध्यान दे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, अब किसान बाजार पर न केवल अपनी नकद फसलें बेचने के लिऐ निर्भर हैं, बल्कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिऐ भी बाजार पर निर्भर हैं। एनएसएसओ के हाल ही में किऐ गऐ सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि कुल कृषि परिवारों के 48 प्रतिशत परिवारों की आय खेती से आती है और बाकी अन्य साधनों से। उदारीकरण का लाभ नहीं उठाया जा सका, इस कारण से लाखों लोग काम की तलाश में गांव छोडने पर मजबूर हैं और प्रत्येक गांव छोडने वाला परिवार भी उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। आज, अधिकतम किसान परिवारों का कम से कम एक

सदस्य कृषि से अलग कोई कार्य कर रहा है, उन्हें भी आहार की बढती लागत से हानि होती है क्योंकि वे उपभोक्ता बन चुके हैं।

मंडल कमीशन और पंचायती राज ने पूरा सामाजिक परिदृश्य, राजनीति और गांव की पारंपरिक शक्ति के ढांचे को सदा के लिऐ बदल दिया है। आरक्षण की राजनीति ने समाज के कई वर्गों में भेद कर दिऐ हैं और अब उनकी पहचान जाति आधारित नौकरी के आरक्षण के लिऐ हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है, जबकि कृषि व्यवसाय चिंता का विषय बनता जा रहा है।

जाति के आधार पर राजनीति करने वाले किसान नेता का भारतीय राजनीति में कोई महत्व नहीं रहा है। यह मान कर की किसान एक महत्वपूर्ण राजनैतिक शक्ति नहीं है, इस कारण सभी राजनैतिक दलों में कोई भी किसान नेता नजर नहीं आता है। नेतागिरी उन व्यक्तियों को सौंपी जा रही है जिन्होंने कभी खेती नहीं की न ही वे कृषि से प्राप्त आय से अपना घर चलाते हैं, बल्कि उनके अपने कारोबार हैं, शहरों में रहते हैं और उनके बच्चे विदेशों में नौकरियां करते हैं। किसानों को ऐसे नेताओं पर जल्दी विश्वास नहीं होता है, इसलिऐ किसानों के आंदोलन कहीं पर सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरी तरफ शहरी मतदाताओं की किसान आंदोलन के प्रति सहानुभूति भी कपट है। यह भ्रम तब तक ही रहता है जब तक मुद्रास्फीति कम रहती है।

नेता ऐसी जटील समस्याओं का समाधान का वादा करते हैं, इस कारण से अधिकतम किसान उनके बहकावे में आ जाते हैं। अधिकतम किसानों के समूह या तो राजनैतिक गठबंधन वाले हैं अथवा उनका राजनीति संबंधी एजेंडा होता है और ऐसा लुभावना धोषणापत्र जारी करते हैं जो लागू नहीं हो सकता। ये धोषणापत्र अधिकतम विवादित उद्देश्यों से भरे होते हैं जैसे उपकरणों पर सब्सिडी, सी 2.50 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैविक खेती, निशचित खरीद, नकद ट्रांसफर, अनिवार्य जिंस अधिनियम, सुरक्षित आय, ऋण माफी, जनवितरण प्रणाली जारी रखना, सार्वभौमिक मूल आय अथवा सभी के लिऐ स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा इत्यादि। किंतु किसान इन मांगों के परिणाम समझ नहीं पाते, बल्कि यह आशा करते हैं उनके जीवन में सुधार होगा। किसान सरकार से वादे पूरे करने की आशा नहीं रखते हैं। लुभावने वादों से जैसे कृषि ऋण माफ करने से सरकारें तो गिरती नहीं रहेंगी बल्कि आने वाले समय में कई प्रकार की नई चुनौतियां उभर आऐंगी, जैसे मतदान के दिनों में आशा से अधिक घृणा देखने को अधिक मिलती है।

किसान अपनी एक स्थाई पहचान बनाने में सक्षम नहीं हैं और किसी का विरोध करने के लिऐ किसी भी दल के प्रति निष्ठा प्रकट कर देता है। कार्ल मार्क्स ने हताश होकर किसानों के लिऐ 'आलू का बोरा' शब्द उपयोग किऐ हैं, क्योंकि वे केवल कुछ विशेष मुद्दों पर ही संगठित होते हैं और वापिस अपने खेतों में लोट जाते हैं। इस प्रकार से राजनीति से गहन परिवर्तन करने का कोई साधन नजर नहीं आता बल्कि यह स्थिति के अनुसार अकसर एक प्रतिकिया होती है।

देश भर के किसान कभी भी एक ही संकट अथवा सभी संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास इकता में बंधने का कोई एक ही कारण नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वे अलग–अलग

समय पर अलग क्षेत्रों में भिन्न फसलें उगाते हैं, कुछ किसानों को लाभ हो जाता है और अन्य को हानि उठानी पडती है। चुनी हुई फसलों की रियायतों से किसानों के कुछ वर्ग को लाभ मिल जाता है। गांव की राजनीति भी अलग प्रकार से हो रही है, यह पंचायत के चुनाव में कई उम्मीदवारों के खडे होने से पता चलता है कि वहां पंचायत की कुछ सिटों के लिऐ बडी संख्या में उम्मीदवार लड़ते हैं। इसके अतिरिक्त किसान लगभग प्रत्येक डेढ़ वर्ष में विभिन्न चुनावों में भाग लेते रहते हैं, जैसे, पंचायत, जिला परिषद, विधानसभा अथवा संसद के चुनाव। इस कारण से किसानों का कोध कहीं न कहीं निकल जाता है और उनमें इसे एक निर्णायक कांति में नहीं बदल पाते। किसानों के आंदोलन की आवाज किसी परिणाम को प्राप्त करने से पहले ही दब जाती है।

किंतु, यह स्पष्ट संदेश है कि किसान एकजुट होकर किसी को भी सत्ता में ला सकते हैं अथवा सत्ता से बाहर कर सकते हैं। किसानों को सपने दिखाऐ जाते हैं और जब ये पूरे नहीं होते तो वैसा ही होता है जैसा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य–प्रदेश जैसे राज्यों में परिणाम सामने आऐ हैं। यह भी जानना आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी के विरूद्ध दिऐ गऐ जनमत का अर्थ यह नहीं की उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। यह तो दो दलों का मुकाबला था, किंतु वर्ष 2019 के आम चुनाव में कई क्षेत्रीय दल चुनावों में भाग लेंगे। जैसे तेलांगना में किसानों के वोटों का बंटवारा हुआ, कुछ वोट मुख्य दलों को और अधिकतम वोट क्षेत्रीय दलों को मिले हैं। नेता के बिना आंदोलन और किसानों की लंबे समय की शिकायतों को एक देशभर में प्रभावी बनाने के लिऐ कांग्रेस को लाभ मिला है। अब ऐसे दल को चाहिऐ की वह एक ऐसे किसान नेता को आगे लाऐ जो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है। यह समय भारतीय राजनीति के लिऐ एक अतिमहत्वपूर्ण समय है।

– अजय वीर जाखड़
अध्यक्ष, भारत कृषक समाज
@ajayvirjakhar

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

मोदी राज में किसान : डबल आमद या डबल आफत ?

* श्री योगेन्द्र यादव

अध्याय एक : किसान विरोधी सरकार ?

1.1 कुछ सवाल जिनका जवाब मिलना चाहिए

क्या मोदी सरकार इस देश के इतिहास की सबसे किसान विरोधी सरकार है ? अगर आप से यह सवाल पूछा जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? यह पुस्तक आपसे इस सवाल पर संवाद करने के लिए लिखी गई है।

पिछले चार साल में इन पंक्तियों के लेखक ने इस देश के कोने–कोने में गांव, खेती, किसानी के सवाल पर यात्राएं की हैं। इस दौरान हर तरह के किसानों के सुख–दुख को देखा है। खेती–किसानी से जुड़े सब वर्ग के जानकारों से बात की है। जब–जब उनसे मोदी सरकार के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो अलग–अलग जवाब मिलते हैं। अकसर कई सवाल सुनने को मिले हैं:

- एक साधारण, भोला–भाला किसान पूछता है: मोदी जी किसान विरोधी कैसे हैं ? वे तो आजकल हमेशा किसान की ही बात करते हैं ?
- गांव का पढ़ा–लिखा किसान पूछता है: मोदी जी तो कहते हैं कि जितना इस सरकार ने किसानों के लिए किया है उतना किसी ने नहीं किया। वो तो बहुत योजनाएं गिनवाते हैं। डबल आमदनी, लागत का दुगना दाम, नीम कोटेड यूरिया और पता नहीं क्या–क्या। आप बिलकुल उलटा कह रहे हैं। मतलब उनकी सरकार ने कुछ भी अच्छा नहीं किया?
- किसान कार्यकर्ता पूछता है: इसमें तो शक नहीं कि मोदी सरकार किसान–विरोधी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस देश की सभी सरकारें किसान–विरोधी रही हैं ? यह सरकार अन्य सरकारों से ज्यादा किसान–विरोधी कैसे है ?
- गांव और खेती की समझ रखने वाला पत्रकार पूछता है: क्या आप किसानों की दुर्दशा के लिए सिर्फ इसी सरकार को दोषी ठहराएंगे ? जब मैं इस सरकार के मंत्रियों और अफसरों से पूछता हूं तो वे कहते है कि पिछली सरकार ने इतनी खराब हालत विरासत में दी थी, हम क्या करते ?
- कृषि विशेषज्ञ पूछता है: सरकार को दोष देना आसान है लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सारी व्यवस्था ही किसान–विरोधी है, इतिहास की धारा ही किसान के विरूद्ध है ? कोई सरकार इसमें क्या कर सकती थी ?
- पढ़े–लिखे शहरी लोग और पत्रकार पूछते हैं: आप सिर्फ किसान की बात क्यों करते हैं ? बाकी लोग भी तो हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। गांव और शहर, दोनों जगह क्या किसान से भी ज्यादा गरीब लोग नहीं हैं ? क्या सरकार को सभी वर्गों में संतुलन की कोशिश नहीं करनी चाहिए ?

हो सकता है आपके मन में भी इनमें से कोई सवाल हो, या फिर इन जैसा कोई और सवाल। हो सकता है आप भी सोचते हों कि मोदी सरकार के विरूद्ध इन बातों में कितनी सच्चाई है ? हो सकता है आंप भी खोजते हों कि किसी एक जगह इन सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, सभी बातों के सही तथ्य मिल जाएं, प्रमाण मिल जाएं।

यह पुस्तिका इसी उद्देश्य से लिखी गइ है। सबसे पहले हम एक शुरूआती शंका का समाधान करेंगे। उसके बाद मोदी सरकार के किसान संबंधी कामकाज को चार हिस्सों में बांटकर उसका मूल्यांकन। अंत में इस सवाल पर विचार किया गया है कि इस दौरान किसानों की दुर्दशा के

लिए किस हद तक मोदी सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है। क्या मोदी सरकार वाकई देश की सबसे किसान–विरोधी सरकार है ?

1.2 जवाब प्रचार से नहीं, प्रमाण से मिलेगा

शरूआत एक बिलकुल साधारण सवाल से। जो भी व्यक्ति अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, उसे जरूर लगता है कि यह सरकार किसानों के प्रति पहले से ज्यादा ध्यान दे रही है। अखबारों में बड़े–बड़े विज्ञापन आते हैं। हर महीने सरकार किसानों के लिए कोई 'ऐतिहासिक' घोषणा करती है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार–बार किसानों का जिक्र करते हैं और किसान की हालत सुधारने के लिए अपने काम गिनाते हैं। क्या पहले किसी सरकार ने किसानों पर इतना ध्यान दिया था ? क्या और कोई प्रधानमंत्री हुआ है जिसे किसानों की इतनी चिंता थी ? ऐसे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को किसान–विरोधी बताना कहां तक उचित है ?

किसी सरकार का मूल्यांकन उसके नाम से नहीं उसके काम से होना चाहिए। आजकल विज्ञापन का युग है। अकसर कंपनियां अपने घटिया माल को बेचने के लिए बड़े–बड़े और लुभावने विज्ञापन का इस्तेमाल करती हैं। समझदार लोग कहेंगे कि कोई भी माल सिर्फ विज्ञापन देखकर नहीं खरीदना चाहिए। हमें खुद माल की जांच करनी चाहिए और जिन लोगों ने उसका पहले प्रयोग किया है उनसे पूछना चाहिए। यही बात सरकार पर भी लागू होती है। आजकल सरकारों के विज्ञापन बड़े–बड़े विशेषज्ञ बनाते हैं। जो लोग साबुन, तेल, कपड़ा और मकान बेचने के विज्ञापन बनाते हैं वैसे ही लोग सरकारों के काम की बिक्री भी करते हैं। इन विशेषज्ञों का धंधा है झूठ को सच बताना, राई का पहाड़ बनाना, दिन को रात दिखाना।

इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री आजकल किसान के बारे में बहुत चिंता जता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री शुरू से किसान के बारे में चिंतित रहे हैं या कि अब जाकर किसान के बारे में चिंता जताने पर मजबूर हुए हैं ? प्रधानमंत्री को किसान की चिंता है या किसान के वोट की ? प्रधानमंत्री को किसान की खुशहाली की चिंता है या सिर्फ अगला चुनाव जीतने की ? पहली नजर में तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री को गुजरात के चुनाव में धक्का लगने के बाद किसान के लिए चिंता पैदा हुई है। गुजरात में उनकी पार्टी चुनाव तो जीत गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पिछड़ गई थी। उसके बाद उत्तर–प्रदेश और राजस्थान में हुए लोकसभा उपचुनावों में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तमाम जनमत सर्वेक्षण दिखा रहे हैं कि किसानों का असंतोष बीजेपी के लिए अगले चुनाव में भारी पड़ सकता है। 2017 के बाद से देशभर में बड़े–बड़े किसान आंदोलन हुए हैं, जिन्होंने सरकार को खेती किसानी के सवाल पर घेरा है। उसके बाद से ही मोदी सरकार ने किसान के सवाल पर बड़ी घोषणाएं शुरू कीं। सरकारी प्रचारतंत्र इस काम में दिन–रात जुटा हुआ है।

1.3 इसलिए विधिवत सत्यापन जरूरी है

इस सवाल पर सच और झूठ का फैसला सिर्फ सरकार का प्रचार देखकर या सिर्फ विरोधियों के आरोप सुनकर नहीं किया जा सकता। किसकी नीयत क्या है, इसका हम अनुमान ही लगा

सकते हैं, जांच नहीं कर सकते। इसलिए इस सवाल पर सच–झूठ का फैसला करने के लिए जरूरी है कि हम सभी तथ्यों की व्यवस्थित रूप से जांच करें और उस आधार पर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालें।

इस पुस्तिका में यही प्रयास किया गया है। अलग–अलग अध्याय में मोदी राज के दौरान किसान की अवस्था के बारे में सभी प्रमुख वादों और दावों, आरोपों और प्रत्यारोपों का सत्यापन किया गया है। अगले अध्याय में हम भारतीय जनता पार्टी के 2014 के घोषणापत्र में किए गए वादों की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले घोषणापत्र में किए गए वादों की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले घोषणापत्र के प्रमुख वादे गिनाए गए हैं। फिर पड़ताल की गई है कि इनमें से कौन से वादे किस हद तक पूरे किए गए। इनमें से सबसे प्रमुख वादे यानी किसान को लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने के वादे की विस्तार से जांच की गई है। तीसरे अध्याय में वादों से आगे चलकर मोदी सरकार के कुछ प्रमुख दावों की जांच की गई है। यहां सिंचाई, फसल बीमा योजना, कृषि ऋण के साथ–साथ नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड और ई–नैम जैसे दावों की प्रमाण सहित जांच की गई है।

चौथे अध्याय में हम देखेंगे कि क्या मोदी सरकार अपने कार्यकाल में किसानों पर आए संकट के वक्त उनके काम आई ? यहां हम तीन प्रमुख संकट की जांच करेंगे – राष्ट्रव्यापी सूखा, बाजार में भाव का गिरना और नोटबंदी।

पांचवें अध्याय में हम इस सरकार पर लगे कुछ प्रमुख आरोपों की जांच करेंगे। आरोप यह है कि इस सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाना तो दूर, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। यहां हम खेती की बढ़ती लागत, निर्यात में गिरावट, मनरेगा के संकुचन, पशुपालन पर धक्के, किसान की भूमि के अधिग्रहण और आदिवासी किसान के वनाधिकार पर हमले जैसे आरोपों की जांच करेंगे।

छठे अध्याय में हम मोदी सरकार के सबसे प्रमुख नारे यानी किसानों की आमदनी डबल करने की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले तो समझेंगे कि इस नारे का अर्थ क्या है, इसकी समीक्षा कैसे की जाए। फिर इस आधार पर सरकार ने जो कुछ किया है उसकी जांच करेंगे। अंतिम दो अध्याय में हम बचे हुए दो प्रश्नों पर गौर करेंगे। सातवें अध्याय में हम पूछेंगे कि मोदी राज में किसान की दुर्दशा के लिए क्या वाकई मोदी सरकार ही जिम्मेवार थी ? यहां हम सरकार के पक्ष में दिए जाने वाले पांच प्रमुख तर्कों की जांच करेंगे। अंतिम अध्याय में हम सरकार की नीति, उसकी नीयत और उसकी राजनीति का खुलासा करेंगे।

अध्याय दो : चुनावी वादों का क्या हुआ ?

2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी किसानों में बहुत लोकप्रिय नहीं थी। उसके पुराने प्रभाव के इलाकों से बाहर किसान बीजेपी को शक की निगाह से देखते थे, उसे शहरी और व्यापारियों की पार्टी समझते थे। इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में किसानों से बढ़–चढ़ कर वादे किए थे। उस समय प्रधानमंत्री पद

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2018-20
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2018-20

प्रकाशन की तिथि : 1 जनवरी, 2019
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–1,
तारीख 4 एवं 5, जनवरी 2019

के दावेदार श्री नरेंद्र मोदी अपनी हर चुनावी सभा में किसानों को लेकर बीजेपी की योजनाओं के बारे में जमकर बोलते थे। आज पलटकर देखें तो ये सब वादे दो श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। एक तो वो वादे हैं जिन्हें बीजेपी सत्ता में आने के बाद भूल गई है, या जिनसे मुकर गई है। दूसरी श्रेणी में वो वादे हैं जिन पर सरकार ने कुछ काम करने के दावे किए हैं। इस अध्याय में हम पहली श्रेणी के वादे का ब्योरा देंगे।

2.1 घोषणापत्र में किसानों से बड़े–बड़े वादे किये थे

बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में 'कृषि – विज्ञान, उत्पादकता और उसका पारितोषक' शीर्षक से खेती के बारे में और किसानों से कई वादे किए गए थे। 'कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता' देने, 'किसानों की आय और ग्रामीण इलाकों के विकास' में वृद्धि के वादे के साथ–साथ बीजेपी ने देश के किसानों से कई छोटे–छोटे वादे किए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वादा था कि 'यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लागत का 50 प्रतिशत लाभ हो।' बीजेपी की सभी चुनावी रैलियों में श्री नरेंद्र मोदी इस वादे का खासतौर पर जिक्र करते थे और किसान की तमाम लागत गिनाते हुए कहते थे कि उनकी सरकार इस पूरी लागत में 50 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी।

(शेष भाग अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा)

---

* अध्यक्ष, स्वराज इंडिया

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

नव–वर्ष 2019 की हार्दिक शुभकामनाऐं

भारत कृषक समाज की ओर से अपने सभी सदस्यगणों, शुभ चिन्तकों तथा कृषक समाचार के पाठकों को नव–वर्ष की ढ़ेर सारी शुभकामनाऐं और समाज आशा करता है कि नव–वर्ष 2019 आप सभी के जीवन में खुशहाली लाऐगा तथा हमारे किसान भाइयों को समृद्ध बनाऐगा।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in. वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।